the fold of minimum operational capacity; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) Minimum economic scales of operation in respect of 65 industries have already been announced. It is the constant endeavour of Government to facilitate operation of industrial units at economic scales of production. The identification of industries to be brought under the scheme of re-endorsement of industrial capacity with reference to minimum economic scales, is a continuing exercise.

Visits of industrial and business delegations from abroad

*155. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of the industrial and business delegations from abroad who visited India to date since the announcement of liberal import and industrial policy by Government; and

(b) the outcome of their visits to India?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) A large number of industrial and business delegations from various countries visited India during the year 1985-86 and held discussions with their counterparts in India. These discussions were held at various levels, both private and official, and also through the form of joint business councils, joint commission meetings, etc. It is difficult to correlate these visits with the liberalisation measures announced. Broader areas of economic cooperation were discused, which would form the basis of concretisation of proposals for transfer of technology, upgradation of technology, increase in exports and joint ventures. However, it is not possible to specifically quantify the outcome of such discussions.

कोयले की राज्यवार मांग

* 156. **श्री मीर्जा ईर्शादबेग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की वार्षिक मांग और पूर्ति की राज्यवार स्थिति क्या है और उसका क्षेत्रवार उत्पादन कितना है;

(ख) इस संबंध में कम आपूर्ति यदि कोई हो तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में गुजरात सरकार की क्या मांग है;

(घ) क्या गुजरात वाणिज्य मंडल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी मांग को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख गया है।

विवरण

(क) से (ङ) विभिन्न राज्यों की मांगों का मूल्यांकन संबंधित प्रायोजन प्राधिकारी करते हैं। प्रायोजन अधिकारी राज्य-वार नहीं हैं, बल्कि वे उद्योग-वार हैं अर्थात् तकनीकी विकास महानिदेशालय, इंडियन शूगर मिल्स ऐसोसिएशन, इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन फार टेक्स्टाइल मिल्स, आदि। इसलिए मांगों का केवल सेक्टरवार मूल्यांकन किया जाता है और वे प्रायोजित होती हैं। कोयला कंपनियां, उपभोक्ताओं को प्रायोजित मात्रा के प्रस्ताव भेजती हैं जिसे उपभोक्ता सड़क से अथवा रेल से अथवा दोनों से उठा सकता है। राज्यों में स्थित लघु-उद्योगों की जरूरतों के प्रायोजन के लिए रेलवे

ने राज्य सरकारों को वैगनों के कोटे दिए हैं। फिर भी, उपभोक्ताओं को रेल द्वारा कोयले की सप्लाई मांग की तुलना में कम रहती है। इसका कारण है– वैगनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना और रेल द्वारा कोयले के लदान में अड़चनें। इसके अतिरिक्त, रेलवे के "प्राथमिकता यातायात अनुसूची" में उल्लिखित रेल-संचलन में प्राथमिकता के अनुसार कोयला उच्च प्राथमिकता के आधार पर इस्पात कारखानों, बिजली घरों, सीमेन्ट कारखानों, आदि को भेजा जाता है। रेल द्वारा कोयले की संचलन में कम प्राथमिकता वाले अन्य उपभोक्ताओं को रेल द्वारा कम कोयला मिलता है। परन्तु, रेल द्वारा कोयला ले जाने में जो कमी रह जाती है, उसे सड़क द्वारा ले जाने की अनुमति दी जाती है।

चूंकि विभिन्न उपभोक्ता-क्षेत्र के लिए प्रायोजन अधिकारी अलग-अलग हैं, इस लिए गुजरात और अन्य राज्यों में स्थित विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की मांग के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1985-86 के दौरान कोयले का राज्यवार उत्पादन निम्नलिखित है :–

(आंकड़े मिलियन टनों में)

राज्य	उत्पादन
पश्चिम बंगाल	19.36
बिहार	54.32
उड़ीसा	6.04
महाराष्ट्र	11.57
मध्य प्रदेश	42.56
उत्तर प्रदेश	3.86
आंध्र प्रदेश	15.70
असम	0.85
जम्मू और कश्मीर	0.03
	154.29

वर्ष 1985-86 के दौरान कोल इंडिया लि० से कोयले का राज्यवार प्रेषण निम्नलिखित है :–

(आंकड़े मिलियन टनों में)

राज्य	प्रेषण
बिहार	18.04
पश्चिम बंगाल	13.68
उत्तर प्रदेश	18.39
उड़ीसा	4.94
मध्य प्रदेश	17.98
महाराष्ट्र	13.60
गुजरात	10.67
राजस्थान	2.42
दिल्ली	3.75
पंजाब	4.86
हरियाणा	2.81
तमिलनाडु	4.16
आंध्र प्रदेश	0.78
कर्नाटक	0.99
केरल	0.19
जम्मू और काश्मीर	0.09
हिमाचल प्रदेश	0.05
चंडीगढ़	0.03
असम	0.42
अन्य	0.52

गुजरात वाणिज्य-मंडल ने एक अभिवेदन भेजा है जो कोयले की सप्लाई और भुगतान की कुछ क्रिया-विधियों, बाक्स "एन" वैगनों से संबंधित समस्याओं और कोयले की अपर्याप्त सप्लाई-विशेषकर कपड़ा मिलों-के संबंध में है। इस मामले पर कोयला विभाग और रेलवे के बीच चर्चा हुई थी और यह निर्णय हुआ था कि उपभोक्ताओं की मदद के लिए गुजरात में कोल इंडिया के स्टाकयार्डों को 4 रेकों की तदर्थ सहायता दी जाए। इनमें से तीन रेक पहले ही भेजे जा चुके हैं।